राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

स्वतंत्र प्रभात

जो लिखेगा, वही टिकेगा

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. (UHIN/2009/34814) (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, बुधवार, 03 जून2026
वर्ष 16, अंक 91, पृष्ट 04, मूल्य: 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाजियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

तुलसी नगर स्टेशन पर हाईकोर्ट सख्त...03

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: 100 करोड़ की ज़मीन 10 करोड़ में बेच दी...04

शासक ही हमलावर बन गए...भतीजे अभिषेक पर अटैक से बिफरीं ममता बनर्जी

● पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की कड़ी निंदा हो रही है. अब तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. ममता ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए

पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की कड़ी निंदा हो रही है. राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हर कोई इसे गलत ठहरा रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और अखिलेश यादव इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं. अब तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. ममता ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए।

घटना के तुरंत बाद, तृणमूल ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी. एक पोस्ट में यह बताया गया कि अभिषेक हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी दिवंगत तृणमूल कार्यकर्ता के परिवार के साथ खड़े रहे थे. इस पोस्ट को रीट्वीट करते हुए ममता बनर्जी ने लिखा, अब तो शासक ही हमलावर बन गए हैं. BJP को शर्म आनी चाहिए. तृणमूल ने कहा, बीजेपी का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। अभिषेक पर हुए हमले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था कितनी तेजी से चरमरा रही है. क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही सुशासन है? उन्होंने आगे कहा कि पूरी दुनिया इस घटना को देख रही है।

गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए: डेरेक ओ'ब्रायन

इससे पहले टीएमसी नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने बंगाल की बीजेपी सरकार को घेरते हुए हमला बोला. उन्होंने एक्स पर लिखा 'अभी बंगाल में क्या हो रहा है? दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टीअखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा नेता, चुनाव के बाद हुई हिंसा में बीजेपी द्वारा मारे गए एक व्यक्ति के परिवार से मिलने गए थे. अभिषेक बनर्जी पर कुछ बीजेपी समर्थकों ने भीड़ बनाकर हमला किया. उनकी जान खतरे में है। पुलिस कहां है? वोटों की गिनती के दिन सुरक्षा क्यों हटा ली गई थी? गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए'

अखिलेश ने बताया नफरत की राजनीति

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा 'बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक प्रमुख नेता अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला करवाकर राज्य की अराजक बीजेपी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वह नफरत भरी, नकारात्मक और हिंसक राजनीति करने के अलावा कुछ भी करने में असमर्थ है. इतने संवेदनशील माहौल में भी पुलिस की तैनाती न होना, किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है. यह बेहद निंदनीय है! '

बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को नकारा

इस घटना के संबंध में बीजेपी का दावा है कि सोनारपुर में हुई घटनाओं से उसका कोई लेना-देना नहीं है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी इस घटना में शामिल नहीं है. पिछले पांच वर्षों में दक्षिण 24 परगना में तृणमूल ने जिस तरह के अत्याचार किए हैं, उसे देखते हुए अगरबीजेपी चाहती, तो तृणमूल के नेता अभी अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पाते. यह पूरी तरह से बीजेपी के संयम बरतने का ही नतीजा है कि तृणमूल के नेता इस तरह आजादी से घूम-फिर पा रहे हैं।

अभिषेक ने लगाया आरोप

सोनारपुर, दक्षिण 24 परगना में स्थित है. यह कोलकाता के करीब है. अभिषेक बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों को पहले से जानकारी देने के बावजूद, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई. उन्होंने कहा, 'मैं इस जगह से तब तक नहीं हटूंगा, जब तक पुलिस और सुरक्षा बल यहां सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर देते. वे घरों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और वे मुझे मार डालना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज उनके हेलमेट की वजह से ही उनका सिर बच पाया; वरना कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती थी. विपक्षी दलों को चुनौती देते हुए अभिषेक बनर्जी ने यह साफ कर दिया कि ज्ञस्ष्ट इस तरह के कायरतापूर्ण हमलों से डरने वाली नहीं है और वह लोगों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी।

दिल्ली के साकेत में भर-भराकर गिरा पांच मंजिला मकान

● मलबे में कई लोगों के दबने की आशंका

राजधानी दिल्ली के साकेत स्थित सैदुलअजाइब में शनिवार रात एक मकान ढह गया। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया।

दिल्ली के साकेत में शनिवार रात मकान ढहा।

मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका।

स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान शुरू किया।

नई दिल्ली। राजधानी में शनिवार की शाम को साकेत स्थित सैदुलअजाइब में पांच मंजिला मकान गिरने से मलबे में कई लोगों के दबने की खबर से हड़कंप मच गया। फिलहाल, स्थानीय लोगों ने बचाव राहत कार्य शुरू कर दिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, मकान गिरने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू कर दिया। वहीं, पुलिस को भी सूचना दी गई। राजधानी दिल्ली के साकेत स्थित सैदुल्लाजाब इलाके में शनिवार रात एक बहुमंजिला इमारत पूरी तरह से ढह गई। यह घटना साकेत मेट्रो स्टेशन के पास हुई। दिल्ली फायर सर्विस को शाम 7:44 बजे सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची फायर टीम ने पुष्टि की कि एक पांच मंजिला इमारत गिर गई है, जिसके मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है।

राजधानी दिल्ली के साकेत क्षेत्र में शनिवार शाम एक मकान के गिरने की सूचना मिली। दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि उनको शाम करीब 7:44 बजे यह कॉल मिली। इसके बाद तुरंत फायर टेंडर मौके पर रवाना कर दिए गए। वहीं, स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सभी राहत कार्य तेजी से करना आरंभ कर दिया है। इसके तुरंत बाद घटनास्थल पर शुरू में 3 वाटर टेंडर और एक आईआरटी रवाना किए गए। बाद में एक और वाटर टेंडर और एक लाइट वैन भेजी गई। रेस्क्यू और राहत कार्य तेजी से चल रहा है। स्थानीय लोगों ने भी तुरंत बचाव कार्य में सहयोग शुरू कर दिया था। अभी तक हताहतों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फायर सर्विस, पुलिस और अन्य एजेंसियां मौके पर सक्रिय हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मकान गिरने के समय अंदर कुछ लोगों के मौजूद होने की आशंका है, इसी वजह से मलबे में कई लोगों के दबे होने की संभावना जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और अन्य बचाव एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गई है. मलबे को हटाने का काम जारी है और फंसे लोगों की तलाश की जा रही है. फिलहाल, यह साफ नहीं हो पाया है कि इमारत गिरने की वजह क्या रही है। शुरुआती जांच में निर्माण की स्थिति और इमारत की मजबूती को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है. अधिकारियों का कहना है कि मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता है. महरौली पुलिस स्टेशन इलाके में हुए इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल है. बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटा है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है।

संक्षिप्त ख़बरें

सिद्धार्थनगर: शीशम के पेड़ की टहनी कटते युवक को लगा करंट, मौके पर मौत

सिद्धार्थनगर। जिले के खेसरहा थाना क्षेत्र के भैसा गांव में शनिवार को करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सोनू लोधी (25) पुत्र राममिलन लोधी निवासी ग्राम भैसा के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, सोनू गांव के बाहर स्थित शीशम के पेड़ की टहनी काट रहे थे। इसी दौरान टहनी ऊपर से गुजर रही 11000 वोल्ट की बिजली लाइन से छू गई, जिससे सोनू गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से घायल युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेसरहा पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

खोए और चोरी हुए मोबाइल हाथ में देख खिल उठे चेहरे

पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में पूर्वी जिला पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत 532 लोगों को उनके खोए व चोरी हुए मोबाइल लौटाए। वसुंधरा एन्क्लेव स्थित महाराजा अग्रसेन कॉलेज में पुलिस ने इस संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया। स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव, संयुक्त पुलिस आयुक्त पूर्वी रेंज अजीत कुमार सिंगला व डीसीपी राजीव कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। **ठगी से बचने की दी जानकारी** पुलिस अधिकारियों ने लोगों को साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी निवेश योजनाओं और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के बारे में जानकारी दी। साथ ही साइबर अपराध की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 का उपयोग करने की अपील की गई। स्पेशल सीपी ने कहा कि ऑपरेशन विश्वास दिल्ली पुलिस की सेवा-उन्मुख और पारदर्शी कार्यशैली का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि खोई या चोरी हुई संपत्ति को उसके वास्तविक मालिक तक पहुंचाना पुलिस और जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करता है।

अटेंडेंस की वजह से छात्र को एग्जाम में बैठने से रोका... सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

» सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें कहा गया था कि कानून के छात्रों को केवल अपर्याप्त उपस्थिति के आधार पर परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकता. बीसीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्देशों को चुनौती देते हुए नोटिस जारी किया. यह फैसला कानूनी शिक्षा में उपस्थिति के महत्व पर बहस को फिर से सामने ला रहा है

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली हाईकोर्ट के पिछले साल पारित उस निर्देश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि कानून के छात्रों को केवल अपर्याप्त उपस्थिति के आधार पर परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकता. साथ ही न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया था. याचिका में कानून के छात्रों के लिए अनिवार्य उपस्थिति संबंधी दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों को चुनौती दी गई थी. जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि 21 जुलाई तक जवाब दाखिल करें, नोटिस जारी करें. इस बीच विवादित फैसले के पैरा 249 का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा

क्या था मामला?

हाईकोर्ट ने ये आदेश 2016 के एक दुखद मामले की सुनवाई के दौरान दिया था. इस मामले में एमिटी यूनिवर्सिटी के एक छात्र की आत्महत्या का जिक्र था. बताया गया था कि कम उपस्थिति के कारण छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली थी. जिससे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इस मामले को संज्ञान में लिया और मार्च 2017 में इसे दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था

हाईकोर्ट ने क्या कहा था?

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि कानूनी शिक्षा में व्यापक और व्यावहारिक सोच अपनाना जरूरी है. अदालत ने माना कि पढ़ाई सिर्फ रटने या केवल कक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए. कानून की पढ़ाई में उसे समझना, व्यवहार

में लागू करना और सही तरीके से पेश करना भी उतना ही जरूरी है. बेंच ने सिर्फ उपस्थिति के आधार पर बनाए गए सख्त नियमों पर भी सवाल उठाए थे. कोर्ट ने कहा कि अच्छी शिक्षा का मतलब केवल कक्षा में मौजूद रहना नहीं है अदालत ने कहा कि मूट कोर्ट, सेमिनार, मॉक पार्लियामेंट, वाद-विवाद और दूसरी कानूनी गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी भी पढ़ाई का अहम हिस्सा है. इसलिए इन गतिविधियों के लिए छात्रों को अकादमिक क्रेडिट दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने ये भी कहा कि अनिवार्य उपस्थिति के कठोर नियम कई बार छात्रों की रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच पर असर डालते हैं, खासकर तब जब उन्हें कक्षा से अपेक्षित सीख नहीं मिल रही हो

चकबंदी के बाद जमीन पर कब्जे का आरोप

पीड़िता ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार

ललितपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बानपुर निवासी एक व्यक्ति ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे और जान से मारने की धमकियों का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम बानपुर निवासी रामस्वरूप पुत्र गरीबा ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि गांव में स्थित उसकी जमीन की चकबंदी लेखपाल एवं कानूनगो द्वारा की गई थी। आरोप है कि चकबंदी के बाद उसकी जमीन के हिस्से पर गांव के कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया। पीड़ित के अनुसार जब उसने कब्जा हटाने की बात कही तो आरोपियों द्वारा उसे और उसके परिवार के साथ अभद्रता की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिससे परिवार दहशत में है। रामस्वरूप ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर कब्जा हटवाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शिकायत पत्र के साथ पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र और चकबंदी संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां भी संलग्न की गई हैं।

फर्जी कॉलेज की शिकायत से मचा हड़कंप, जांच की मांग

● डीएमएलटी छात्र ने जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा ज्ञापन

● दस्तावेजों की सत्यता पर उठाए सवाल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ललितपुर। शिक्षा के नाम पर कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद छात्रों में हड़कंप मच गया है। आजादपुरा निवासी एक छात्र ने स्थानीय संस्थान एसएन हेल्थकेयर एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के खिलाफ डीआईओएस को शिकायती पत्र सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। छात्र का आरोप है कि संस्थान द्वारा दिए जा रहे दस्तावेजों की प्रामाणिकता संदिग्ध है और समय पर जरूरी कागजात भी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता सुमित पुत्र कैलाश नारायण निवासी आजादपुरा ने बताया कि वह उक्त संस्थान से डीएमएलटी (डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी) का कोर्स कर रहा है। आरोप है कि कॉलेज द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है, जिससे उनकी वैधता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित छात्र का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन से कई बार संपर्क करने के बावजूद आवश्यक दस्तावेज समय पर नहीं दिए गए। कुछ कागजात लंबे इंतजार और लगातार दबाव के बाद मिले, जबकि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अब तक लंबित हैं। छात्र ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन छात्रों को लगातार टालता रहा, जिससे उनका समय और धन दोनों बर्बाद हो रहे हैं। शिकायतकर्ता ने जिला विद्यालय निरीक्षक से मांग की है कि संस्थान की मान्यता, दस्तावेजों और संचालन की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि अन्य छात्रों का भविष्य प्रभावित होने से बचाया जा सके। मामले को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शिकायत पत्र प्राप्त कर जांच की प्रक्रिया शुरू किए जाने की चर्चा है। छात्र और उसके परिजन अब प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।

त्विषा शर्मा मौत मामले में गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द

» त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत केस में पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद सीबीआई टीम गुरुवार को उनके भोपाल स्थित घर पहुंची। उनको हिरासत में ले लिया है। वहीं, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद एजेंसी ने पूछताछ और मामले की जांच तेज कर दी है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को त्विषा शर्मा मौत मामले में मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। जबलपुर में बुधवार को सुनवाई करते हुए अवकाशकालीन न्यायाधीश देवनारायण मिश्रा ने कहा कि मामले के तथ्यों और लगाए गए आरोपों को देखते हुए भोपाल की सत्र अदालत द्वारा 15 मई 2026 को दी गई अग्रिम जमानत को निरस्त किया जाता है। अदालत ने दहेज प्रताड़ना और अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं स्वीकार कर लीं।

त्विषा शर्मा के परिवार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आखिरकार त्विषा मामले में न्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि गिरिबाला सिंह 36 वर्षो तक न्यायिक सेवा में रही हैं, इसलिए कानून के प्रति सम्मान दिखाते हुए उन्हें सीबीआई के सामने आत्मसमर्पण कर जांच में सहयोग करना चाहिए। सीबीआई ने सोमवार को पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की मौत की जांच अपने हाथ में ली थी। त्विषा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में फांसी के फंदे पर लटकी मिली थीं। सीबीआई ने मध्य प्रदेश पुलिस की एफआईआर को दोबारा दर्ज करते हुए पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया है।

जिलाधिकारी ने दो पूर्ति निरीक्षकों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी, जन समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही पर कार्रवाई

सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जी एन ने शासकीय दायित्वों के निर्वहन में गम्भीर लापरवाही बरते जाने, दिये गये निर्देशो का पालन नहीं करने तथा शासन के महत्वपूर्ण निर्देश के क्रम में प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित होकर पूर्वाह्न 10 से 12 के मध्य जनसुनवाई के दिये गये निर्देश का पालन न करने अक्सर तहसील में अनुपस्थित रहने, वर्तमान वैश्विक परिदृष्य में भी पेट्रोल पम्पों व गैस एजेंसियो पर शिथिल पर्यवेक्षण करने समय से आई0 जी0 आर0 एस0 व अन्य जन समस्याओं का निस्तारण न करने शिकायतकर्ताओं/ आमजन से समुचित व्यवहार न करने जैसे शासकीय कार्यो में गम्भीर लापरवाही बरते जाने के कारण प्रियंका कश्यप, पूर्ति निरीक्षक उसका बाजार व माला गुप्ता, पूर्ति निरीक्षक लोटन को जिलाधिकारी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टी प्रदान की गई है। उक्त आशय की जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी, देवेन्द्र प्रताप सिंह ने अपने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया है।

सिद्धारमैया का कर्नाटक सीएम पद से इस्तीफा, डीके शिवकुमार का रास्ता साफ़

» कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद से सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस अब समाप्त हो गया है. राज्यपाल ने सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है

कर्नाटक की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राजभवन जाकर राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके सचिव को सीएम पद का इस्तीफा सौंपा और कहा कि उनके आलाकमान ने जो कहा वो किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस हाईकमान के निर्देश के बाद अब डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के नए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ़ हो गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राजभवन जाकर राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा।

इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया ने कहा कि उनके आलाकमान ने जो कहा उन्होंने वो किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'हाई कमान ने मुझसे राज्यसभा में जाने के लिए कहा। लेकिन, मैंने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मेरी राष्ट्रीय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। लोगों ने मुझे पाँच साल के लिए चुना है। अभी दो साल और बाकी हैं। तब तक, मैं यहीं सेवा करूँगा।' इस्तीफ़ा देने के कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि वह एक नए मुख्यमंत्री के लिए जगह बना रहे हैं, लेकिन उनकी राष्ट्रीय स्तर पर कोई भूमिका निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिद्धारमैया ने कहा, 'जब हाई कमान मुझसे इस्तीफ़ा देने को कहेगा, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। दो दिन पहले हाई कमान ने मुझसे पद छोड़ने को कहा था। इसलिए, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है।'

सिद्धारमैया ने कहा, 'मैंने लोक भवन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया है।' उन्होंने कहा, 'राज्यपाल शहर में नहीं हैं। उनके दफ़्तर ने मुझे बताया कि राज्यपाल शाम को लौटेंगे। इसलिए, मैंने इस्तीफ़ा पत्र उनके दफ़्तर में सौंप दिया।' सिद्धारमैया ने कहा, 'मैं एक राजनेता हूँ। मेरा मानना है कि संविधान ही हमारा धर्म है और मतदाता हमारे लिए भगवान के समान हैं।' कर्नाटक कांग्रेस नेता एच.के. पाटिल ने शुक्रवार को जानकारी दी कि कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को शाम 4 बजे आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद पार्टी के भीतर उत्पन्न सभी मुद्दों का समाधान हो चुका है और अब संगठन में एकता बनी हुई है।'

हिंदी पत्रकारिता की गौरवशाली यात्रा और बदलते आयाम

हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में 30 मई का दिन एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित है। इसी दिन वर्ष 1826 में हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र उदन्त मार्तण्ड का प्रकाशन आरंभ हुआ था। इस युगांतरकारी घटना की स्मृति में प्रत्येक वर्ष संपूर्ण देश में हिंदी पत्रकारिता दिवस अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक जागरूकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक पावन अवसर है। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत विदेशी भाषाओं से हुई थी। उस प्रारंभिक दौर में हिंदी भाषी समाज की समस्याओं और उनके मौलिक विचारों को राष्ट्रीय स्तर पर अभिव्यक्त करने के लिए किसी सशक्त माध्यम का अभाव था। इस शून्यता को समझते हुए पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने तत्कालीन भारत की राजधानी कोलकाता से उदन्त मार्तण्ड नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र को प्रकाशित करने का दृढ़ संकल्प लिया। इस पत्र का सर्वप्रथम अंक 30 मई 1826 को जनमानस के सम्मुख आया। उस आदि काल में इस पत्र की लगभग 500 प्रतियां मुद्रित की जाती थीं और इसका वितरण प्रत्येक मंगलवार को किया जाता था। अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों और औपनिवेशिक सरकार के असहयोग के कारण इसका नियमित प्रकाशन लंबे समय तक जारी नहीं रह सका, परंतु इस संक्षिप्त प्रयास ने हिंदी पत्रकारिता की एक अत्यंत मजबूत नींव रख दी। राष्ट्रीय अभिलेखागार जैसे संस्थानों में सुरक्षित ऐतिहासिक दस्तावेज हमें आज भी बताते हैं कि किस प्रकार इन शुरुआती पत्रों ने राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था।

उदन्त मार्तण्ड शब्द का शाब्दिक अर्थ उगता हुआ सूर्य होता है। जिस प्रकार उदित होता हुआ सूर्य सघन अंधकार को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार पत्रकारिता भी समाज में व्याप्त अज्ञान, अंधविश्वास और शोषण को उजागर कर चेतना का प्रकाश फैलाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गौरवशाली इतिहास में, विशेष रूप से 1857 की महान क्रांति के समय और उसके पश्चात, हिंदी पत्रकारिता ने विदेशी शासन के विरुद्ध प्रखर जनमत तैयार करने में अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाई। मंगल पांडे और वीर कुंवर सिंह जैसे महान राष्ट्रभक्तों के अप्रतिम संघर्ष से प्रेरणा लेते हुए, देश के विभिन्न हिस्सों से निकलने वाले समाचार पत्रों ने दमनकारी नीतियों का खुलकर विरोध किया। सत्य की राह पर चलने वाले निर्भीक पत्रकारों को बार बार जेल की अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ती थीं और भारी आर्थिक दंड भुगतना पड़ता था। इन तमाम कठोर अवरोधों के बावजूद हिंदी पत्रकारिता ने अपने परम कर्तव्य से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। बाल गंगाधर तिलक और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे तपस्वी पत्रकारों ने पत्रकारिता को राष्ट्रसेवा का एक पवित्र माध्यम बनाया और अपनी निर्भीक कलम से जनता को स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूक किया।

हिंदी पत्रकारिता का बहुआयामी विकास कभी भी केवल राजनीतिक विषयों तक ही सीमित नहीं रहा। इसने भारतीय साहित्य, काव्य शास्त्र और विशेषकर दोहा जैसे पारंपरिक छंदों को सहेजने, संस्कृति, ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं, शिक्षा, किसानों की समस्याओं और विभिन्न सामाजिक विसंगतियों जैसे संवेदनशील विषयों को भी राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। अनेक साहित्यकारों ने अपनी कथाओं को प्रकाशन के लिए तैयार करते हुए पत्रकारिता के माध्यम से समाज को एक सकारात्मक दिशा दी। जिस कालखंड में सूचनाएं केवल बड़े शहरों तक सीमित रहती थीं, उस दौर में हिंदी पत्रकारिता ने देश के सुदूर क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में मजबूत सेतु का कार्य किया। पर्यावरण के निरंतर गिरते स्तर पर भी इस पत्रकारिता ने कठोर प्रहार किया है। अरावली और छत्तीसगढ़ के जंगलों की अंधाधुंध कटाई और उससे शहरी तापमान पर पड़ने वाले घातक प्रभावों की उत्कृष्ट रिपोर्टिंग ने आम लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत किया है। जंगलों के अनवरत विनाश के कारण उत्पन्न होते इस भीषण संकट को मुख्यधारा की बहस का हिस्सा बनाने में हिंदी पत्रों की भूमिका सदैव सराहनीय रही है।

जैसे जैसे समय का चक्र तेजी से परिवर्तित हुआ, पत्रकारिता के बाह्य और आंतरिक स्वरूप में भी व्यापक बदलाव आते गए। नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों ने पत्रकारिता को अत्यंत तीव्र और व्यापक बना दिया है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और अंतर्जाल के अभूतपूर्व आगमन ने सूचनाओं के प्रसारण की प्रक्रिया को रूपांतरित कर दिया है। इस आधुनिक अंकीय पत्रकारिता के दौर में हिंदी भाषा की वैश्विक पहुंच कई गुना बढ़ चुकी है। आज करोड़ों लोग अपने चलभाष यंत्रों और संगणक के माध्यम से पल पल में हिंदी समाचार पढ़ते और देखते हैं। आर्थिक जगत की जटिल खबरों ने भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान पाया है। आज का आम नागरिक प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम और पारस्परिक निधियों में निवेश से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हिंदी वित्तीय पत्रकारिता पर पूरा भरोसा करता है।

इस आधुनिक पत्रकारिता के समक्ष वर्तमान समय में कई अत्यंत गंभीर चुनौतियां भी उठ खड़ी हुई हैं। समाचारों को सबसे तेज प्रसारित करने की इस अंधी होड़ में कई बार परम सत्य और प्रामाणिक तथ्यों की अनदेखी होने लगती है। भ्रामक सूचनाओं का तीव्र प्रसार और विभिन्न प्रकार के दबाव वर्तमान पत्रकारिता की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभरे हैं, जो इसकी विश्वसनीयता को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सर्वसाधारण तक पूर्ण निष्पक्ष जानकारी पहुंचाना है। इसलिए आज इस बात की महती आवश्यकता है कि पत्रकारिता अपनी गंभीर नैतिक जिम्मेदारियों को पुनः समझे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकारिता को न्यायसंगत रूप से चौथा स्तंभ स्वीकार किया गया है। यदि हमारी पत्रकारिता पूरी तरह स्वतंत्र और निर्भीक बनी रहेगी, तभी हमारा लोकतंत्र भी मजबूत रहेगा। एक सच्चा पत्रकार हमेशा समाज के शोषित वर्ग और सत्ता के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेतु की भांति कार्य करता है।

वर्तमान समय में हिंदी पत्रकारिता की सीमाएं केवल भारत तक आबद्ध नहीं रह गई हैं, बल्कि विश्व के अनेक देशों में बसे प्रवासी भारतीय भी आधुनिक संचार माध्यमों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अंतर्जाल और अंकीय मंचों ने हिंदी पत्रकारिता को एक विशिष्ट वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाई है। अनेक हिंदी समाचार जालस्थल और सामाजिक मंच आज वैश्विक स्तर पर करोड़ों लोगों तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। इसके अतिरिक्त, इस विराट क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी भी बहुत तेजी से बढ़ी है। अनेक साहसी महिला पत्रकार राजनीति, अपराध और पर्यावरण जैसे जटिल मुद्दों पर निष्पक्ष समाचार संकलन कर रही हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस केवल अतीत की स्मृतियों को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि भविष्य के निर्माण के प्रति संकल्प लेने का महापर्व भी है। हमें एक ऐसी सकारात्मक पत्रकारिता को बढ़ावा देना होगा जो समाज में आपसी सौहार्द और रचनात्मक परिवर्तन ला सके। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग करते हुए सत्य और सामाजिक जिम्मेदारी को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए। एक सच्चा पत्रकार वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी निष्पक्ष बना रहे। उदन्त मार्तण्ड से आरंभ हुई यह यात्रा आज एक विराट वटवृक्ष का रूप ले चुकी है, जो हमें यह निरंतर संदेश देती है कि कलम की शक्ति संसार की किसी भी अन्य शक्ति से अनंत गुना प्रभावशाली होती है।

महेन्द्र तिवारी

युवाओं के भविष्य पर डाका: पेपर लीक, अरबों का खेल और 'उम्मीदों' का अंतहीन स्कैम

संपादक/लेखक: राजीव शुक्ला

आज के दौर में देश के युवाओं के साथ होने वाला सबसे बड़ा और संगठित स्कैम 'पेपर लीक' बन चुका है। यह संकट सिर्फ एक परीक्षा के रद्द होने भर का नहीं है, बल्कि इसके पीछे करोड़ों युवाओं के सपनों, समय और उनके परिवारों की गाढ़ी कमाई की सुनियोजित लूट का एक ऐसा चक्रव्यूह है, जिसका सच बेहद खौफनाक है।

100 करोड़ का गणित: आवेदन के नाम पर धन-उगाही

यदि पुलिस और चुनिंदा शिक्षक भर्तियों को छोड़ दिया जाए, तो अमूमन किसी भी विभाग में 500 से अधिक पद नहीं निकलते। चतुर्थ श्रेणी या लेखपाल जैसी भर्तियों का उदाहरण लें, तो चंद सौ या हजार पदों के लिए 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक आवेदन आते हैं। यह स्थिति स्वतः स्पष्ट करती है कि 99% से अधिक आवेदकों के हिस्से सिर्फ असफलता ही आनी है। लेकिन खेल इसके पीछे के 'परीक्षा शुल्क' का है। यदि प्रति छात्र औसतन 400 रुपये भी फीस मानी जाए और 25 लाख आवेदन आएं, तो यह रकम 100 करोड़ रुपये बनती है।

तमाशा देखिए:पेपर लीक होता है, परीक्षा रद्द होती है। युवा अपना समय, किराया और उम्मीदें गंवाकर वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सरकारी आयोग के अध्यक्ष को अपना पूरा वेतन मिल चुका होता है और परीक्षा कराने वाली प्राइवेट एजेंसियां अपना 80% तक भुगतान डकार चुकी होती हैं। नुकसान हुआ तो सिर्फ देश के युवा का।

कोचिंग हब: असफलता को भुनाने वाला बाज़ार

इस बड़े असफल समूह को निशाना बनाकर आज देश में अरबों रुपयों का 'कोचिंग व्यवसाय' खड़ा किया गया है। कोचिंग संस्थान भी भली-भांति जानते हैं कि नौकरियां चुनिंदा लोगों को ही मिलनी हैं। इसलिए, अपनी साख बचाने के लिए ये संस्थान दोहरी चाल चलते हैं:

परीक्षा से पहले: कई बार व्यवस्था में सेंध लगाने या अनुचित लाभ उठाने के प्रयास।

परीक्षा के बाद: गड़बड़ी का बढ़-चढ़कर प्रचार, ताकि जब छात्र असफल हों, तो उनका ध्यान कोचिंग की नाकामी से हटकर व्यवस्था की कमी पर चला जाए।

यह सरकारी तंत्र को क्लीन चिट देने का बहाना नहीं है, बल्कि यह समझने का जरिया है कि युवा चारों तरफ से बिचौलियों से घिरा हुआ है।

बुनियाद पर चोट: सरकारी बनाम निजी स्कूलों का गोरखधंधा

इस स्कैम की जड़ें और गहरी तब हो जाती हैं जब हम स्कूली शिक्षा के स्तर पर देखते हैं। सरकारी विद्यालयों के विलय (Merger) की नीति एक बड़ी सामाजिक समस्या बन रही है। गाँवों के स्कूल बंद होने से गरीब परिवारों के बच्चे, विशेषकर बालिकाएं, शिक्षा से महरूम हो रही हैं, क्योंकि सुरक्षा कारणों से लोग बेटियों को दूर के स्कूलों में भेजने से कतराते हैं। दूसरी ओर, निजी स्कूलों का एक बड़ा गोरखधंधा चल रहा है। अधिकांश बड़े निजी शिक्षण संस्थानों के पीछे किसी न किसी रसूखदार 'नेताजी' का हाथ होता है। अब ज़रा सोचिए:

एक तरफ सरकारी स्कूल से सिर्फ 'साक्षर होने वाला गरीब का बच्चा है। दूसरी तरफ महंगे निजी स्कूल से 'शिक्षित' होने वाला अमीर का बच्चा है। जब इन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा (Competition) कराई जाएगी, तो परिणाम पहले से तय है। अमीर और अमीर होता जाएगा, और गरीब का बच्चा उसी दुष्चक्र में फंसा रहेगा।

राजनीति का मौन और अंतिम धोखा

यदि इन तमाम झंझावातों, असमानताओं और अभावों को पार करके कोई गरीब या मध्यमवर्गीय युवा भर्ती परीक्षा तक पहुंच भी जाता है, तो वहाँ उसे 'पेपर लीक' का अंतिम और सबसे क्रूर धोखा मिलता है। फॉर्म भरने से लेकर कोचिंग की फीस और शहरों में रहने के खर्च के नाम पर लाखों रुपये गंवाने के बाद युवाओं के हिस्से केवल निराशा या फिर से 'जीरो' से तैयारी करने की मजबूरी आती है। इस पूरे तंत्र में सिस्टम के शीर्ष पर बैठे लोग सुरक्षित हैं–आयोग के अध्यक्ष अपना वेतन लेते हैं, राजनेता रैलियों में अपनी पीठ थपथपाते हैं और निजी एजेंसियां अपना मुनाफा समेटती हैं। पेपर लीक जैसे संवेदनशील और युवाओं के जीवन को तबाह करने वाले मुद्दों पर सत्ताधीशों का मौन या ढीला रवैया यह साफ संकेत देता है कि इस सामूहिक लूट का कोई न कोई सिरा व्यवस्था के रक्षकों को भी पोषित कर रहा है। यह धोखा सिर्फ एक छात्र को नहीं, बल्कि सीधे इस देश के भविष्य को दिया जा रहा है।

भारतीय युवाओं के मस्तिष्क को संकुचित करता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट के भारतीय संदर्भ में जहां जनसंख्या 141 करोड़ हो चुकी है और बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार है ज्यादा प्रयोग से लोगों की नौकरियां जाने का बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह बात दुनिया के बड़े अरबपति कारोबारी टेस्ला और एक्स के कारोबारी एलन मस्क ने स्टार्टअप के एक कार्यक्रम में फ्रांस में महत्वपूर्ण अंदाज में कहीं, भविष्य के लिए यह बात एकदम सटीक एवं सार्थक है। एक अन्य अरबपति कारोबारी इयान बैंक्स ने भी इस पर गंभीर चिंता जताई है। यह बात सभी विकासशील देशों के लिए भी लागू हो सकती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नफ्ज़ पढ़कर आपके मस्तिष्क की बात तुरंत पकड़कर उस पर अमल करने लगेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पल्स रेट द्वारा आपके मन की हर बात जानने में सक्षम हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक को वैज्ञानिकों ने मानव की सहायता के लिए और देश की बेहतरी के लिए अविष्कार किया है।

अभी तक तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इजरायल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में काफी आगे पर अब खाड़ी के देशों विगत 5 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति केवल तेल के कुए पर न रह कर अन्य योजनाओं पर भी काम करना शुरू कर दिया है और आश्चर्यजनक रूप से यूएई, सऊदीअरबिया, कतर, मिस्त्र ,जॉर्डन, मोरक्को और अन्य देशों में यूरोप की तुलना में अब और ज्यादा खर्च करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक को अपने देश में बहुत मजबूत बना लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितने फायदे हैं उससे ज्यादा विकासशील देशों के लिए यह नुकसान देह भी हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी पल्स रीडिंग और मानसिक विचारधारा को केवल थंब इंप्रेशन में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिवाइस पढ़ कर उस पर अमल कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी से अमेरिका तथा यूरोपीय देश अब तक दुश्मन की अनेक सूचनाएं बड़ी आसानी से प्राप्त कर उसका सामरिक उपयोग करने में लगे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग रूस अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर मिसाइल दागने में यूक्रेन यूक्रेन के विरुद्ध कर रहा है और अब तक यूक्रेन यूरोपीय तथा नाटो देश की मदद से इसी तकनीक के सहारे रूस के विरुद्ध अब तक टिका हुआ है वैसे तो यूक्रेन और रूस का युद्ध में काफी नुकसान हुआ है पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर उपयोग दोनों देश एक दूसरे पर कर रहे हैं।

विकासशील देशों में इस टेक्नोलॉजी का विकास अभी काफी एडवांस नहीं है इन परिस्थितियों में उनके लिए उनके सामरिक महत्व की चीजें छुपाना दुश्मन देशों के सामने कठिन हो जाएगा और उनकी खुफिया जानकारी शक्तिशाली देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक सूत्र प्राप्त करने के बाद ही पूरी प्राप्त कर सकते हैं. खाड़ी के देश जिनमें सऊदी अरबिया, कतर ,मिस्त्र, जॉर्डन, यूएई अपने बजट का 34% बढ़ा हुआ हिस्सा एआई तकनीक पर लगातार कर रहे हैं। खाड़ी के देश इस टेक्नोलॉजी का उपयोग इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यह उनकी भविष्य की योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे वे तेल की कमाई से हटकर अन्य साधनों से अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकेंद्य यूं एई पहला देश है जिसने 2017 ने इस तकनीक को अपनाया था इसके बाद खाड़ी के देशों में अब टेक्नोलॉजी को अपनाने में होड़ हो गई हैद्य यह सभी देश एआई टेक्नोलॉजी पर लगभग 3 अरब डॉलर खर्च कर चुके हैंद्य दूसरी तरफ यदि इसका इस्तेमाल अति विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया गया तो इसका दुरुपयोग जिन देशों के पास इन टेक्नोलॉजी से एडवांस टेक्नोलॉजी है वह पूरी जानकारी निकालने में सक्षम होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग यूरोपीय देश न सिर्फ सामरिक महत्व की चीजों में कर रहे हैं बल्कि मेडिकल साइंस और अंतरिक्ष विज्ञान में भी पूरी तरह हो रहा है और इससे बहुत फायदे भी मिल रहे हैंद्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव प्रजाति के लिए जितना फायदेमंद है दूसरी तरफ उतना ही नुकसान दे और इससे वैश्विक शांति को खतरा भी हो सकता हैद्य राइट एक्टिविस्ट मानते हैं कि रोबोट की तरह इस तरह की विज्ञान पर आधारित चीजें माननीय प्रजाति को खत्म कर सकती है बल्कि उनकी चिंता डेटा सुरक्षा प्रपो गेंडा सर्विलांस के विरुद्ध होने वाले नुकसान पर भी ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर खाड़ी के देशों ने एआई के इस्तेमाल पर दिशा निर्देश तय कर उसे जारी किया है हालांकि इस पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है फिर भी इसका दुरुपयोग होने से मानव को खतरा भी हो सकता है यह एक वैश्विक चिंता की बात है।

संजीव ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक

चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या घुसपैठियों के बस जाने तथा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भारतीय नागरिक बनकर लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बनने की आशंकाओं के बीच, चुनाव आयोग ने वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना और केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करना था। हालांकि, इस प्रक्रिया का देश के अधिकांश विपक्षी दलों ने तीखा विरोध किया। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि एसआईआर अभियान केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इसे लोकतंत्र और मताधिकार पर हमला बताते हुए न केवल देशभर में विरोध प्रदर्शन किए गए, बल्कि चुनाव आयोग की इस कार्यवाही को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई।

बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आए, जो आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। परिणामस्वरूप लाखों नाम मतदाता सूची से हटाए गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर प्रक्रिया लागू की गई, जहां तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कानूनी चुनौती दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वहां भी चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण कार्य पूरा किया। पश्चिम बंगाल में भी लाखों लोग दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके, जिसके चलते वे मतदान से वंचित रहे। इसके बावजूद राज्य में रिकॉर्ड 92 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। देशभर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को संवैधानिक और वैध करार दिया। अदालत ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती और निष्पक्ष चुनावों के लिए मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण आवश्यक और न्यायसंगत है।

सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता की जांच कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर संदेह हो, तो आयोग उसका नाम मतदाता सूची से हटाने अथवा शामिल न करने का अधिकार रखता है। हालांकि, किसी व्यक्ति की नागरिकता पर अंतिम निर्णय केवल नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ही कर सकेंगे। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान संदेह के आधार पर हटाए गए नामों को सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाए और यदि संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिक पाए जाते हैं, तो उनके नाम पुनः मतदाता सूची में शामिल किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग चार दशकों बाद देशभर की मतदाता सूचियों की व्यापक और पारदर्शी समीक्षा संभव हो सकेगी। इससे न केवल चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ेगी, बल्कि लोकतंत्र की नींव भी और अधिक मजबूत होगी। **अरविंद रावल**

दैनिक राशिफल

मेष राशि आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी मिलेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
शुभ रंग: लाल **शुभ अंक:** 9

वृषभ राशि आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। **शुभ रंग:** सफेद **शुभ अंक:** 6

मिथुन राशि नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। किसी बात को लेकर मन थोड़ा विचलित रह सकता है। **शुभ रंग:** हरा **शुभ अंक:** 5

कर्क राशि परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। व्यापार में सावधानी से निर्णय लें। यात्रा के योग बन रहे हैं। पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। **शुभ रंग:** सिल्वर **शुभ अंक:** 2

सिंह राशि आज सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। **शुभ रंग:** सुनहरा **शुभ अंक:** 1

कन्या राशि दिन सामान्य रहेगा लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। निवेश सोच-समझकर करें। **शुभ रंग:** नीला **शुभ अंक:** 7

तुला राशि आज किस्मत आपका साथ दे सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे। घर में मांगलिक चर्चा हो सकती है।
शुभ रंग: गुलाबी **शुभ अंक:** 4

वृश्चिक राशि मन में नए विचार आएंगे। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। किसी करीबी से मतभेद समाप्त हो सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।
शुभ रंग: मैरून **शुभ अंक:** 8

धनु राशि धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। करियर में नई दिशा मिलने के योग हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा।
शुभ रंग: पीला **शुभ अंक:** 3

मकर राशि आज धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
शुभ रंग: भूरा **शुभ अंक:** 10

कुंभ राशि नई पहचान और संपर्क से लाभ मिलेगा। नौकरी में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
शुभ रंग: आसमानी **शुभ अंक:** 11

मीन राशि आज मानसिक शांति बनी रहेगी। कला और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। व्यापार में लाभ और परिवार में सुखद वातावरण रहेगा।
शुभ रंग: बैंगनी **शुभ अंक:** 12

लखनऊ में रूफटॉप सोलर ऊर्जा का बढ़ता विस्तार: एक नई हरित क्रांति

आज सम्पूर्ण विश्व ऊर्जा संकट, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा, मानवता के लिए एक आशा की किरण बनकर उभरी है। भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और नीतियों ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आज देश के प्रमुख सोलर शहरों में अपनी पहचान बना रही है और यह परिवर्तन वास्तव में एक नई हरित क्रांति का संकेत है। लखनऊ में रूफटॉप सोलर ऊर्जा का वर्तमान विस्तार किसी चमत्कार से कम नहीं है। वर्ष 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2025 तक केवल लखनऊ जिले में लगभग 4,271 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके थे। इसके बाद यह विकास और अधिक तीव्र हो गया। अप्रैल 2026 तक लखनऊ में 87,000 से अधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन दर्ज किए गए, जिससे यह देश के अग्रणी सौर जिलों में शामिल हो गया। अगस्त 2025 से जनवरी 2026 के बीच लखनऊ उत्तर प्रदेश के उन शीर्ष 10 जिलों में रहा जहाँ सर्वाधिक नए रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए गए। उत्तर प्रदेश ने भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। दिसंबर 2025 तक राज्य में 3 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके थे। इसके बाद मार्च 2026 तक यह संख्या लगभग 4.48 लाख तक पहुँच गई तथा राज्य की कुल रूफटॉप सौर क्षमता 1,524 मेगावाट से अधिक हो गई। यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी सौर ऊर्जा राज्यों में स्थापित करती है। मेरे लिए यह विषय केवल तकनीकी या प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व का विषय रहा है। वर्ष 2015 में जब उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2015 की सोलर पॉलिसी लागू हुई, तब मैंने यह अनुभव किया कि भविष्य में बढ़ती जनसंख्या और ऊर्जा आवश्यकता को देखते हुए सौर ऊर्जा ही सबसे व्यवहारिक समाधान होगी। उसी समय मैंने अपने निजी आवास की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कराया। यह संयंत्र गुरुग्राम की एक सौर ऊर्जा फर्म द्वारा लगाया गया था। उस समय लखनऊ में यह एक अत्यंत नया प्रयोग था और मुझे शहर में पहला नेट-मीटर लगवाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। उस दौर में अधिकांश लोग सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक नहीं थे। लोगों को यह विश्वास दिलाना कठिन था कि घर की छत पर लगने वाला सोलर प्लांट न केवल बिजली बिल को कम कर सकता है बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजकर आय का स्त्रोत भी बन सकता है। परंतु मेरा दृढ़ विश्वास था कि आने वाले वर्षों में सौर ऊर्जा ही शहरी ऊर्जा आत्मनिर्भरता का आधार बनेगी।

मेरा सपना था कि जिस प्रकार लखनऊ की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, आने वाले समय में यह शहर 50 से 60 लाख की आबादी वाला महानगर बनेगा। तब यहाँ 15 लाख से अधिक घर होंगे और यदि प्रत्येक घर की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो जाए, तो केवल लखनऊ शहर में ही 4,500 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन संभव होगा। आज जिस गति से सौर ऊर्जा का विस्तार हो रहा है, उसे देखकर यह सपना अब दूर नहीं लगता। सौर ऊर्जा के प्रति जनजागरूकता फैलाना भी मेरी प्राथमिकता रही। मैंने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सेमीनारों, तकनीकी कार्यशालाओं, शैक्षणिक सम्मेलनों तथा जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए प्रेरित किया। मेरा उद्देश्य केवल तकनीकी जानकारी देना नहीं था, बल्कि समाज में ऊर्जा संरक्षण और हरित विकास की सोच विकसित करना था। आज स्कूल ऑफ़ मैनेजमेंट साइंसेस, लखनऊ, जहाँ मैं महानिदेशक के पद पर कार्यरत हूँ, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक आदर्श मॉडल बन चुका है। संस्थान परिसर में 275 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित है और संस्थान को शत-प्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग की दिशा में विकसित किया जा रहा है। यह न केवल ऊर्जा बचत का उदाहरण है, बल्कि विद्यार्थियों और समाज के लिए एक प्रेरणास्त्रोत भी है।

वर्षवार सोलर रूफ टॉप जोड़ने का डाटा (इङ्क में)

वर्ष	नया जुड़ाव	कुल स्थापना
2015-16	500	500
2016-17	1,000	1,500
2017-18	2,000	3,500
2018-19	4,000	7,500
2019-20	6,000	13,500
2020-21	10,000	23,500
2021-22	18,000	41,500
2022-23	28,000	69,500
2023-24	45,000	114,500
2024-25	75,000	189,500
2025-26	110,000	299,500

लखनऊ में रूफटॉप सोलर विकास के पीछे कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भी रहे हैं। वर्ष 2019 में लागू 'उत्तर प्रदेश नेट मीटरिंग रेगुलेशन' ने उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजने की सुविधा प्रदान की, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा। इसके बाद 'उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022' ने आवासीय रूफटॉप सोलर, सब्सिडी सहायता, सोलर सिटी विकास तथा नेट-मीटरिंग विस्तार को नई गति दी। यदि पिछले दस वर्षों का अध्ययन किया जाए तो वर्ष 2015 से 2019 तक विकास अपेक्षाकृत धीमा था क्योंकि लोगों में जागरूकता कम थी और सोलर संयंत्रों की लागत अधिक थी। वर्ष 2020 से 2022 के बीच सरकारी संस्थानों और व्यावसायिक भवनों में सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ा। इसके बाद प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रत्यक्ष सब्सिडी हस्तांतरण, सरल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तथा नेट-मीटरिंग सुधारों के कारण वर्ष 2023 के बाद आवासीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का तीव्र विस्तार शुरू हो गया। आज लखनऊ स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा परिवर्तन का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन चुका है। रूफटॉप सोलर प्रणाली से लोगों के बिजली बिलों में कमी आ रही है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है तथा ऊर्जा आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। मेरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में लखनऊ 'सोलर स्मार्ट सिटी' के रूप में पूरे देश में नई पहचान स्थापित करेगा और यह हरित क्रांति भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्य टिप्पणी

» 2015-2019 के दौरान सीमित जागरूकता और सब्सिडी की कम पहुँच के कारण रूफटॉप सोलर की वृद्धि धीमी रही

» निम्नलिखित के बाद वृद्धि में तेजी आई:

» यूपी नेट मीटरिंग विनियम 2019,

» यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022,

» पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।

» उत्तर प्रदेश में रूफटॉप सोलर क्षमता ने निम्न स्तर को पार किया:

» वर्ष 2025 में 1,038 मेगावाट,

» वर्ष 2026 में 1,524 मेगावाट।

राज्य स्तरीय संदर्भ आंकड़े (उत्तर प्रदेश)

» प्रारंभिक कार्यान्वयन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में ग्रिड-संयुक्त रूफटॉप सोलर क्षमता लगभग 265 मेगावाट तक

» सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है।

प्रो. (डॉ.) भरत राज सिंह, महानिदेशक, स्कूल ऑफ़ मैनेजमेंट साइंसेस

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2009/34814 मो0 नं0 -9511151254, E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

अचानक भरभरा कर गिरा महुआ का पेड़, एक गंभीर समेत पांच घायल

गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल किया गया रेफर

लंभुआ, सुल्तानपुर। लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के पांडेपुर गांव में शनिवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। गांव के सूरज कुमार, सुरजीत कुमार, शैलेश कुमार, संदीप कुमार, उमेश कुमार और दिव्यांशु गांव में स्थित एक विशाल महुआ के पेड़ के नीचे बैठकर हवा ले रहे थे। इसी दौरान बिना किसी आंधी-पानी या तेज हवा के अचानक महुआ का पेड़ भरभराकर गिर पड़ा। पेड़ गिरने से वहां बैठे युवक उसकी चपेट में आ गए, जिससे पांच लोग घायल हो गए। हादसे में सूरज कुमार को गंभीर चोटें आई, जबकि अन्य चार युवकों को भी चोटें लगीं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एंबुलेंस की सहायता से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंभुआ पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सूरज कुमार की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं अन्य घायलों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार अभय राजपाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना तथा आवश्यक जानकारी प्राप्त की।

प्रहर्ष फाउंडेशन एवं चेतना साहित्य परिषद के तत्वाधान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन संपन्न

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के प्रहर्ष फ़ाउंडेशन एवं चेतना साहित्य परिषद के संयुक्त तत्वावधान में करन भाई सभागार, गांधी भवन, कैसरबाग, लखनऊ में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. आर. पी. मिश्रा उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में टी.पी. हवेलिया एवं रामकृष्ण यादव ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में पद्मश्री डॉ. सुनील जोगी, संजय शौक, डॉ. आदित्य जैन, प्रमोद द्विवेदी, अंशु 'प्रिया' दुबे एवं आलोक रंजन मिश्रा ने अपनी प्रभावशाली काव्य प्रस्तुतियों से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवियों की ओज, हास्य, श्रृंगार एवं संवेदना से भरपूर रचनाओं को श्रोताओं ने खूब सराहा। इस अवसर पर प्रहर्ष फ़ाउंडेशन द्वारा हनुमान प्रसाद गर्ल्स इंटर कॉलेज की मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के निवेदक रामाशंकर दुबे, विपिन शर्मा, डॉ. सुमन दुबे, डॉ. शिव शरण 'कमलेश', एवं सुश्री सुधा गुप्ता की विशेष भूमिका रही।

ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतिंदर सिंह भसीन को ED ने किया गिरफ्तार, धोखाधड़ी से निवेशकों के पैसे हड़पने का आरोप

लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ग्रेटर नोएडा स्थित ग्रैंड वेनिस माल के संचालक सतिंदर सिंह भसीन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने यह कार्रवाई भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (बीआइआइपीएल) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है। ईडी ने पीएमएलए की गाजियाबाद स्थित विशेष अदालत में आरोपित को पेश कर छह जून तक का रिमांड हासिल किया है। सतिंदर सिंह भसीन, क्विंसी भशीन व उनके करीबियों ने रियल स्टेट परियोजनाओं में निवेशकों को मोटा लाभ दिलाने का लालच देकर 1300 करोड़ रुपये का चूना लगाया था। इस मामले को लेकर विभिन्न थानों में निवेशकों की शिकायत पर 80 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे। ईडी ने इन्हीं मुकदमों को आधार बनाकर अपनी जांच शुरू की थी। अभी तक की जांच में यह बात सामने आई है कि निवेशकों से जुटाई गई राशि का उपयोग आरोपित ने परियोजनाओं के निर्माण और विकास में करने के बजाय समूह की विभिन्न कंपनियों और संबद्ध संस्थाओं के जरिए दूसरे उद्देश्यों के लिए डायवर्ट और खर्च किया। इसके चलते आरोपित ने निवेशकों को व्यावसायिक इकाइयों की समय पर डिलीवरी नहीं की और न ही परियोजनाएं पूरी की। वहीं, इस मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने पिछली 15 मई को टिप्पणी की थी कि निवेशकों की रकम लेकर आरोपित ने परियोजना पूरी नहीं की और न ही निवेशकों को संबंधित इकाइयों का कब्जा दिया। इसलिए आरोपित को हिरासत में लिया जाए। इसके बाद ईडी ने शुक्रवार को आरोपित को गिरफ्तार कर शनिवार को उसे विशेष अदालत में पेश कर छह जून तक के लिए रिमांड पर लिया है। वहीं इस मामले में ईडी द्वारा पहले ही सतिंदर सिंह भसीन की राजौरी गार्डन स्थित 44.06 करोड़ रुपये की कोठी को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। ईडी के अनुसार मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य आरोपितों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।

तुलसी नगर स्टेशन पर हाईकोर्ट सख्त

● तीन महीने में फैसला लेने का रेलवे को आदेश, क्षेत्रवासियों में जगी उम्मीद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ/सुलतानपुर। सुलतानपुर जनपद के तुलसी नगर रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों के ठहराव और वर्षों से बंद पड़ी पैसेंजर ट्रेनों के पुनः संचालन को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने उत्तर रेलवे को निर्देश दिया है कि आवेदन प्रस्तुत होने की तिथि से तीन महीने के भीतर तथ्यों का परीक्षण कर इस मामले में सकारण निर्णय लिया जाए। यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय एवं माननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने जनहित याचिका संख्या WPIL 523/2026 अंकित सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य की सुनवाई के दौरान पारित किया। जनहित याचिका स्थानीय अधिवक्ता अंकित सिंह द्वारा क्षेत्रवासियों की समस्या को देखते हुए दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशुतोष सिंह और विजय बहादुर सिंह ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि रेलवे स्टेशन पर करोड़ों रुपये खर्च कर आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद यात्री ट्रेनों का ठहराव न होना जनता के साथ अन्याय है। अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि यह स्थिति संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ग) और 21 के तहत नागरिकों को मिले अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने इन तर्कों को गंभीरता से लेते हुए रेलवे प्रशासन को समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया।

करोड़ों खर्च, फिर भी नहीं रुक रहीं ट्रेनें

याचिका में कहा गया है कि पिछले एक-दो वर्षों में तुलसी नगर स्टेशन के आधुनिकीकरण पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए। स्टेशन पर नया प्लेटफॉर्म, स्काईवॉक, सीढ़ियां और अन्य आधुनिक यात्री सुविधाएं बनाई गईं, लेकिन इसके बावजूद यहां किसी भी महत्वपूर्ण यात्री ट्रेन का ठहराव नहीं हो रहा है। याचिका में इसे लोकधन की बर्बादी बताते हुए रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 11 और 12 का हवाला दिया गया, जिसके तहत आम जनता को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना रेलवे का वैधानिक दायित्व है।

दो लाख आबादी को राहत की उम्मीद

तुलसी नगर रेलवे स्टेशन सुलतानपुर जिले के हरपुर, सजमपुर, पतारखास समेत आजमगढ़ जिले के खंडौरा और कादीपुर क्षेत्र के दर्जनों गांवों की करीब दो लाख आबादी के लिए अहम यातायात केंद्र है।

ट्रेनों के ठहराव न होने से रोजाना रोजगार, व्यापार, शिक्षा और इलाज के लिए अयोध्या, वाराणसी, जौनपुर और लखनऊ आने-जाने वाले सैकड़ों यात्रियों और छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन की खास बात यह भी है कि यह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के अकबरपुर-शाहगंज कट के बेहद करीब स्थित है, जिससे यहां बेहतर इंटर-मॉडल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की संभावनाएं हैं।

इन ट्रेनों के ठहराव की मांग

रेलवे प्रशासन को सौंपे गए प्रतिवेदन में निम्न मांगें प्रमुख रूप से रखी गई हैं–

फिरोजपुर-धनबाद गंगा-सतलज एक्सप्रेस (13307/13308) का नियमित ठहराव

बहराइच-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव

वर्षों से बंद वाराणसी-लखनऊ पैसेंजर ट्रेनों का तत्काल पुनः संचालन

क्षेत्र में खुशी की लहर

हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्षेत्रवासियों और दैनिक यात्रियों में उम्मीद जगी है। लोगों का कहना है कि यदि ट्रेनों का ठहराव शुरू हो जाता है तो हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और क्षेत्र के व्यापार तथा शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

प्रतिबंधित पेड़ो पर आरा चला रहे है लकड़कट्ट

● थाना सकरन क्षेत्र में सरे आम कटे जा रहे हैं प्रतिबंधित (जामुन) पेड़

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सकरन: थाना सकरन क्षेत्र के गांव में लकड़कट्टों ने प्रतिबंधित जामुन के पेड़ों की निर्भीक अवैध कटाई कर दी है। सरे आम हो रही इस कटाई से स्थानीय पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। बड़े जामुन के पेड़ को हाल ही में आरा चलाकर काट दिया गया है। जामुन के पेड़ वन विभाग के नियमों के तहत संरक्षित श्रेणी में आते हैं। इनकी कटाई के लिए वन विभाग की लिखित अनुमति अनिवार्य है, लेकिन थाना सकरन क्षेत्र के गांव में लकड़कट्टे बिना किसी डर के खुले आम इन पेड़ों को काट रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह कोई पहली घटना नहीं है। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से ऐसी अवैध कटाई लगातार जारी है। वन विभाग और पुलिस प्रशासन की उदासीनता से अवैध लकड़कट्टों का हौसला बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने चिंता जताते हुए कहा कि यदि समय रहते रोकथाम नहीं की गई तो पूरे क्षेत्र के जंगल साफ हो जाएंगे। जामुन के पेड़ केवल फल देने वाले ही नहीं, बल्कि मिट्टी के कटाव को रोकने, भूमिगत जल स्तर बनाए रखने और जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बड़े पैमाने पर इनकी कटाई से क्षेत्र में पर्यावरणीय असंतुलन, जल संकट और जैव विविधता के नुकसान की आशंका बढ़ती है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से तुरंत संज्ञान लेने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना यह है कि वन विभाग और थाना सकरन पुलिस इस पर्यावरणीय अपराध पर कितनी तेजी से कार्रवाई करती है।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भारी वाहन पलटा

● डिवाइडर से टकराकर हुआ हादसा, ट्रेलर पर लदे थे ट्रैक्टर; चालक-क्लीनर को आई चोटे

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। पंजाब से असम जा रहा एक भारी वाहन डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि इस हादसे में वाहन चालक और क्लीनर बाल-बाल बच गए और कोई गंभीर हताहत नहीं हुआ। यह घटना दोपहर करीब 12:50 बजे हलियापुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज-03 पर किलोमीटर 80.200 के पास हुई। जानकारी के अनुसार, ट्रैक्टर लदा एक ट्रेलर (PB 65 BC 1765) पंजाब से असम के गुवाहाटी की ओर जा रहा था। बताया गया है कि वाहन के चालक कन्हैया को अचानक नींद की झपकी आ गई। तेज रफ्तार होने के कारण चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और ट्रेलर सीधे डिवाइडर से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर लदा यह ट्रेलर सड़क से नीचे उतरकर पूरी तरह पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही यूपीडा (PEIDA) की रेस्क्यू टीम और एम्बुलेंस महज 5 मिनट के भीतर दोपहर 1 बजकर 02 मिनट पर मौके पर पहुंच गई। वाहन में सवार ड्राइवर कन्हैया (पुत्र मुन्नू लाल, निवासी ददिया, थाना टटिया, जिला फर्रुखाबाद) और उनके साथी सौरव (पुत्र दुर्ग नारायण) को तुरंत बाहर निकाला गया। इस भयानक हादसे में दोनों को सिर्फ मामूली खरोंचें आई। यूपीडा टीम के एएसओ राम चंद्र वर्मा, सेफ्टी टीम और एम्बुलेंस स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को नजदीकी सीएचसी अस्पताल पहुंचाया। वहां पट्टी कराने के बाद दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है।

मारपीट के बाद सबमर्सिबल का बोर किया खराब, पांच पर मुकदमा दर्ज

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के महाखेड़ा गांव की रहने वाली एक महिला ने गांव के पांच लोगों पर मारपीट करने और सबमर्सिबल पंप का बोर खराब करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी गीता ने पुलिस को बताया कि 19 मई को गांव के सत्य प्रकाश, शिवम, संदीप, संजय और मनोज ने उसके साथ मारपीट की। गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद डर के कारण वह अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। आरोप है कि इसी दौरान आरोपियों ने उसके घर के बाहर लगे सबमर्सिबल पंप की पाइप तोड़ दी। बोर में ईंट, पत्थर और कंकड़ डालकर उसे पूरी तरह खराब कर दिया। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

सपा का लंभुआ में जनसमस्याओं पर प्रदर्शन

● राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सुलतानपुर/ लंभुआ- बढ़ती जनसमस्याओं और बदहाल बिजली व्यवस्था को लेकर शनिवार को समाजवादी पार्टी (सपा) कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन जितेंद्र वर्मा उर्फ बाजीगर वर्मा के नेतृत्व में किया गया। सपा नेताओं ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक 7 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम लंभुआ को सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। महंगाई चरम पर है, जिससे गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी और मध्यमवर्गीय परिवार गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनका कहना था कि भाजपा सरकार जनता को राहत देने में पूरी तरह विफल रही है। विधानसभा लंभुआ, तहसील लंभुआ सहित पूरे जनपद में अघोषित बिजली कटौती से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। घंटों बिजली गुल रहने के कारण बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और आम नागरिक इस भीषण गर्मी में परेशान हैं। लगातार बढ़ रहे तापमान के बीच जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने को देश के लगभग 22 लाख प्रतिभाशाली छात्रों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि यह युवाओं के सपनों और उनकी मेहनत पर सीधा हमला है, और भाजपा सरकार की भ्रष्ट व लापरवाह व्यवस्था ने युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। क्षेत्र का किसान इस समय खाद की भारी किल्लत से जूझ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव कृषि व आगामी फसलों पर पड़ रहा है। नहरों में पानी न आने के कारण किसानों को खेतों की सिंचाई करने और पशुओं को पीने के पानी के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आदर्श नगर पंचायत लंभुआ के वार्ड नंबर 4, कृष्णानगर (परसरामपुर) में बिजली आपूर्ति के लिए 100 से 200 मीटर दूर से खुले केबल खींचकर विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जिससे हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि यहां तत्काल बिजली के खंभों (पोल) की व्यवस्था कराई जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्य रूप से सपा लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार यादव (भजन प्रधान), जिला सचिव जसवीर राम, अशोक यादव (लंकेश), राधेश्याम वर्मा, रणजीत यादव पूर्व प्रधान, सत्यनारायण पाल (सचिव), शहाबुद्दीन खान, अमर बहादुर यादव, अनिल यादव, सुग्रीव निषाद (सेक्टर प्रभारी), रमेश कुमार यादव, बृजेश यादव, मुकेश यादव सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और लोहिया वाहिनी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अघोषित विद्युत कटौती से परेशान ग्रामीणो के साथ सपा का विशाल धरना-प्रदर्शन

● उच्चधिकारियों को चेतावनी समाधान ना हुआ तो आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा...

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायबरेली- सतांव-जनपद के 179 हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त भीषण विद्युत संकट एवं अघोषित बिजली कटौती के विरोध में समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को व्यापक धरना-प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार तथा विद्युत विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल शिव गणेश लोधी राजपूत एवं जिलाध्यक्ष इंजीनियर वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता, किसान, महिलाएं और स्थानीय नागरिक 33/11 विद्युत उपकेंद्र गुरुबख्शगंज पहुंचे, जहां उन्होंने धरना देकर अपनी मांगों को बुलंद किया। धरना-स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के दौर में क्षेत्रीय जनता अघोषित विद्युत कटौती, लो-वोल्टेज, बार-बार होने वाली ट्रिपिंग तथा जर्जर विद्युत अवसंरचना की समस्याओं से जूझ रही है। किसानों को सिंचाई कार्यों में गंभीर व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में व्याप्त अव्यवस्था के कारण विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपते हुए क्षेत्र में नए ट्रांसफार्मरों की स्थापना, क्षतिग्रस्त एवं जर्जर विद्युत लाइनों के नवीनीकरण, स्मार्ट मीटर संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण, उपकेंद्रों पर कर्मचारियों की अनिवार्य तैनाती तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की मांग की। जानकारी के मुताबिक जनपद के 179 विधानसभा हरचंदपुर के विधायक राहुल शिव गणेश लोधी राजपूत ने कहा कि बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए जनता को सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना पड़ रहा है, जो शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जनसमस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी व्यापक जनआंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होगी। जबकि कुछ दिनों पूर्व क्षेत्रीय विधायक द्वारा विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की समास्याओं से अवगत कराया था परन्तु फिर भी जब समास्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आज आमजन मानस के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित पैदल मार्च करते हुए धरना प्रदर्शन कर राजपाल को सम्बोधित 10सूत्तीय मांगो के साथ अधिशाषी अभियंता रायबरेली को ज्ञापन सौपा। और कहां की अगर अब भी विभाग विद्युत कटौती आदि पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में आंदोलन के स्वरूप दिया जाएगा धरना-प्रदर्शन में विधानसभा अध्यक्ष राकेश यादव, कृपाशंकर यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू सिंह, मोहम्मद रईस खान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश सिंह, निर्भय सिंह, सुरेश पासवान, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी खीरों पवन पासवान,जम समाजवादी पार्टी अम्बेडकर वाहिनी राष्ट्रीय महासचिव सत्येश गौतम, शिव सिंह यादव, जमील अहमद वरिष्ठ सपा कार्यकर्ता राम बहादुर पासवान, जितेंद्र यादव, दीपू शुक्ला सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। बीते दिन समाजवादी पार्टी 179 विधानसभा हरचंदपुर के विधायक राहुल शिव गणेश लोधी राजपूत द्वारा विद्युत निबंधन उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर विद्युत विभाग की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की थी परंतु इतने दिनों के गुर्जर जाने के बावजूद विभाग के अधिकारीगणों मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जिसके फल स्वरुप आज रायबरेली जनपद के समाजवादी पार्टी पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र की आम जनमानस ने सपा केंद्रीय कार्यालय गुरूबक्सगंज से विद्युत उपकेंद्र 33/11 गुरबक्श गंज तक पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया। सपा के जिला अध्यक्ष इंजीनियर वीरेंद्र यादव वह क्षेत्रीय विधायक राहुल शिव गणेश लोधी राजपूत द्वारा कहां गया कि विभाग के उच्च अधिकारियों ने समय रहते ध्यान नही दिया तो जन आंदोलन किया जाएगा।

पत्रकारिता दिवस पर समाचार वितरकों का हुआ सम्मान

● कलम शक्ति ट्रस्ट की गोष्ठी में वितरकों को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। पत्रकारिता दिवस के अवसर पर शनिवार को कस्बे के एक गेस्ट हाउस में कलम शक्ति ट्रस्ट की ओर से गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाचार पत्र वितरकों को सम्मानित कर उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की गई। वरिष्ठ पत्रकार शेर बहादुर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में दीपप्रकाश शुक्ला ने कहा कि समाचार वितरक पत्रकारिता की एक अहम कड़ी हैं। वे हर मौसम और विषम परिस्थितियों में भी घर-घर अखबार पहुंचाकर लोगों तक समय पर समाचार पहुंचाने का कार्य करते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता गुप्ता ने पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महिलाओं की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। कलम शक्ति ट्रस्ट के अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह ने राहुल शुक्ला, राजन दीक्षित, ननकू, अयोध्या, ओमप्रकाश तिवारी, शिवकुमार शुक्ला, अभिनव और शिव नरेश शर्मा समेत अन्य समाचार वितरकों को शॉल ओढ़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन कवि योगेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर कांग्रेसी नेता अतुल सिंह, दीपेंद्र गुप्ता, बीडीओ गगनदीप सिंह, इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह, रमेश सिंह, विकास सिंह, शिवसागर, अंकुर श्रीवास्तव,जितेंद्र सविता, मोहम्मद परवेज़, कुलदीप सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

दलित महिला का पीछा करने पर युवक पर मामला दर्ज

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दलित महिला ने जगतपुर थाना क्षेत्र निवासी युवक पर पीछा करने और जबरन बात करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि आरोपी उसके मायके के पास का रहने वाला है। वह जब भी दवा लेने के लिए बाहर जाती है आरोपी रास्ते में उसका पीछा करता है और जबरन बात करने का दबाव बनाता है। विरोध करने पर आरोपी जहर खाकर जान देने की धमकी देता है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी संदीप के विरुद्ध संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

लखनऊ में निर्माण के दो दिन में उखड़ने लगी नई सड़क, ग्रामीणों ने उठाए गुणवत्ता पर सवाल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी में सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र की पिपरसंड ग्रामसभा के मजरा गुलालखेड़ा में लोक निर्माण विभाग ने जिस सड़क का निर्माण करवाया है, उसने दो दिन बाद ही परत छोड़ दी है। नई सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि बाबा जय सिंह से गुलालखेड़ा तक बनाई गई सड़क के निर्माण में घोटाला हुआ है। निर्माण के दो दिन बाद ही उखड़ने से इसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार सड़क निर्माण के लिए शासन से धन स्वीकृत हुआ था और लंबे समय के बाद यह कार्य पूरा कराया गया। लेकिन सड़क बनने के कुछ ही घंटों बाद इसकी परतें उखड़ने लगीं। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी की गई है, जिसके चलते नई सड़क जल्द ही क्षतिग्रस्त हो गई।

सड़क की खराब गुणवत्ता को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें साझा कर विरोध दर्ज कराया है। वायरल हो रहे वीडियो और फोटो में सड़क की परतें उखड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही भविष्य में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने की भी अपील की है।

TMC नेता अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की निंदा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर शनिवार को हमले की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निंदा की है। उन्होंने इसको सुनियोजित हमला बताया और शुभेंद्र अधिकारी सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी पर शनिवार को दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में चप्पल, जूते और डंडे को चुनावोत्तर हिंसा बताया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर अपने एक्स हैंडल पर अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि भाजपा नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती है। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था न होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। घोर निंदनीय। गौरतलब है कि सांसद अभिषेक बनर्जी के सोनारपुर पहुंचने से पहले शनिवार को कामलगाजी इलाके में महिलाओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद जैसे ही अभिषेक सोनारपुर में दाखिल हुए विरोध और उग्र हो गया। भीड़ ने उन्हें घेर लिया और लगातार अंडे फेंके गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धक्का-मुक्की और हाथापाई में उनकी घड़ी और चश्मा भी क्षतिग्रस्त हो गए। विरोध के बावजूद अभिषेक अंततः चुनाव बाद हिंसा में मारे गए तृणमूल कार्यकर्ता संजू कर्मकार के घर पहुंचे। वहां उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में 'डबल इंजन सरकार' के नाम पर विपक्षी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि वे वहां से चले जाते तो पीड़ित परिवार और अधिक असुरक्षित हो जाता।

संक्षिप्त खबरें

ईद पर कुर्बानी के लिए लाया गया ऊंट सीसीबरगांव पुलिस ने किया जब्द

इलाके में मची हलचल

असम धेमाजी। 28 मार्च को इस्लाम धर्म के लोगों के ईद-उल-फितर के पवित्र त्योहार है । ईद पर कुर्बानी के विषय पर राज्य विभिन्न चर्चा बिज सीसीबर गांव तहसील के अंतर्गत गेलुवा में पुलिस ने एक ऊंट जब्द करने की खबर ने इलाके में हलचल मच गई। द अर्थ फॉर एवरीवन और आश्रय केयर एंड वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्यों ने सिलापथार पुलिस के साथ मिलकर ऊंट को गेलुवा के हन्नान खान के घर से जब्द कर सीसीबरगांव थाने में ले गया। ख़बर अनुसार ऊंट को ईद में कुर्बानी देने के लिए खारुपेटिया से खरीद कर लाया गया था।

शिवसेना के विभिन्न पदों पर संजीत देवनाथ पुनर्नियुक्त

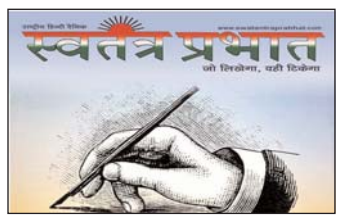

श्रीभूमिः हैलाकांडी- हिंदू हृदयसम्राट श्रद्धेय बालासाहेब ठाकरे द्वारा स्थापित तथा महाराष्ट्र के वर्तमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में हैलाकांडी के संजीत देवनाथ को बराक घाटी प्रमुख एवं शिवसेना प्रभावक संघ के राष्ट्रीय सचिव पद पर पुनर्नियुक्त किया गया है। शिवसेना की राष्ट्रीय समिति के उपनेता तथा शिवसेना प्रभावक संघ के संस्थापक अध्यक्ष श्री अनिल पाडवाल ने संजीत देवनाथ को पुनर्नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके अलावा, संजीत देवनाथ द्वारा संचालित 'छत्रपति शिवाजी सांस्कृतिक मंच' के कार्यों की भी शिवसेना के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सराहना की है। उल्लेखनीय है कि शिवसेना के संस्थापक हिंदू हृदयसम्राट श्रद्धेय बालासाहेब ठाकरे के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर संजीत देवनाथ 1 अक्टूबर 2010 से एक शिवसैनिक के रूप में कार्य करते आ रहे हैं।

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा धूमधाम से मनाई गई बाबू बालेश्वर लाल की 39 वीं पुण्यतिथि

जसराना- ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील जसराना की इकाई ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जनक और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थावीपक स्वर्गीय बाबू बालेश्वर लाल जी की 39वीं पुण्य तिथि पर एक बैठक सम्पन्न की जिसमें उनके जीवन के विचारों को याद किया गया और सभी पत्रकार साथियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किये जिसकी अध्यक्ष तहसील अध्यक्ष शशवीर सिंह चक द्वार की गई और इसमे उपस्थित पत्रकार साथी सुरेश गिरि कोषाध्यक्ष हरदेश कुमार, तहसील महासचिव सुनील कुमार वकील साहब, मीडिया प्रभारी पुष्पेंद्र यादव, सदस्य तेजवीर सिंह सदस्य नरेंद्र कुमार सदस्य सचिन्द्र जैन उपाध्याय सागर गुप्ता सदस्य आदी लोग उपस्थित रहे।

जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार में हजारीबाग पुलिस का औचक निरीक्षण

हजारीबाग, झारखंडः- बीते रात्रि पुलिस अधीक्षक हजारीबाग अमन कुमार के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) के नेतृत्व में हजारीबाग पुलिस द्वारा जिले के दंडाधिकारी की उपस्थिति में जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार, हजारीबाग का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल परिसर के विभिन्न संदिग्ध वार्डो की गहन जांच की गई तथा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। औचक निरीक्षण के दौरान जेल के अंदर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों एवं जेल कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने जेल के भीतर और बाहर सतर्कता बनाए रखने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने तथा सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही हजारीबाग पुलिस से प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मियों को भी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाए रखने के लिए विशेष निर्देश दिए गए। निरीक्षण का उद्देश्य जेल की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकना बताया गया। हजारीबाग पुलिस द्वारा समय-समय पर इस प्रकार के औचक निरीक्षण किए जाते हैं ताकि जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त बनी रहे। मौके पर पुनि सह थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार समेत पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे।

मध्य प्रदेश में 25-25 हजार में दुल्हन लेने आये थे 42 दूल्हे,: हो गये शादी घोटाले के शिकार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। मध्य प्रदेश में शादी के बहाने की गई एक संगठित धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है।इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मध्य प्रदेश के 42 दूल्हे अपनी शादी के दिन तैयार होकर पहुंचे–कुछ चमकीली शेरवानी, गेंदे के फूलों की माला और मिठाइयों से भरे स्टील के डिब्बे लिए हुए। लेकिन दुल्हनें कभी नहीं आईं, और बाद में इन आदमियों को एहसास हुआ कि वे एक नकली शादी के घोटाले का शिकार हो गए हैं। पुलिस के अनुसार, रविवार को देवास में जो कुछ हुआ, वह सिर्फ़ एक वित्तीय धोखाधड़ी का मामला नहीं था, बल्कि उन दर्जनों आदमियों के लिए एक सार्वजनिक अपमान था, जो देवास और आस-पास के ज़िलों के गांवों और छोटे कस्बों से यह मानकर आए थे कि उनकी शादी होने वाली है। शाम तक, जश्न का मैदान गुस्से और अविश्वास के माहौल में बदल गया, जब परिवारों को एहसास हुआ कि वे शायद एक बड़े घोटाले में फंस गए हैं–जिसमें कथित तौर पर इंदौर के एक अनाथ आश्रम से दुल्हनें दिलाने का वादा करके लाखों रुपये ठगे गए थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह मामला शादी के बहाने की गई एक संगठित धोखाधड़ी का है। बैंक नोट प्रेस पुलिस स्टेशन की इंचार्ज प्रीति कटारे ने कहा, 'हमें कई युवकों से शिकायतें मिली हैं। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।' उन्होंने आगे कहा, 'आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी तलाश जारी है। हम उस अनाथ आश्रम से जुड़े दावों की भी पुष्टि कर रहे हैं, जिसके नाम का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया था।' हर दूल्हे ने बिचौलियों को 15,000 से 25,000 रुपये के बीच दिए थे, जिन्होंने देवास में एक 'सामूहिक विवाह समारोह' आयोजित करने का वादा किया था। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें हफ़्तों पहले मोबाइल फ़ोन पर होने वाली दुल्हनों की तस्वीरें दिखाई गई थीं। दूसरों ने दावा किया कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि ये महिलाएँ गरीब या अनाथ परिवारों से हैं और तुरंत शादी करने को तैयार हैं। राहुल, जो हरनियाकलां गाँव से आए थे, ने कहा, 'हममें से हर किसी से रजिस्ट्रेशन फ़ीस के तौर पर 25,000 रुपये देने को कहा गया था। हमें बताया गया था कि दुल्हनें इंदौर के मातृ छाया आश्रम से हैं। जब हमने तस्वीरें माँगीं, तो आयोजकों ने हमें सोशल मीडिया से डाउनलोड की गई मॉडल्स की तस्वीरें भेज दीं। उन्होंने हमसे समारोह से एक दिन पहले देवास पहुँचने को कहा और भरोसा दिलाया कि सामूहिक विवाह अगले दिन सुबह होगा। उन्होंने दहेज का सामान देने का भी वादा किया था। लेकिन जब हम कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे, तो वहाँ कोई नहीं था, और बाद में सभी फ़ोन बंद हो गए,' मीना ने कहा। दूल्हों में से एक, अशोक ने कहा कि उन्हें 'सादे कपड़ों में आने का निर्देश दिया गया था क्योंकि दूल्हे के कपड़े और शादी की सभी रस्में वहीं आयोजित की जाएँगी '। उन्होंने कहा, 'उन्होंने हमसे खास तौर पर कहा था कि पहुँचने से पहले हल्दी या मेहंदी न लगाएँ क्योंकि सभी रस्में कार्यक्रम स्थल पर ही होंगी। ' ओम प्रकाश, जो अपने परिवार के साथ भोपाल से आए थे, ने कहा कि उन्होंने 'उन तस्वीरों में से दुल्हनें चुनीं जो हमें मोबाइल फ़ोन पर भेजी गई थीं '। 'हमने अपने भाई की शादी के लिए ऑनलाइन दस्तावेज़ जमा किए थे। हमारे पहुँचने के बाद, आयोजक हमसे लगातार कहते रहे कि मैडम दुल्हनों के साथ रास्ते में हैं, लेकिन आधी रात तक कोई नहीं आया,' उन पुरुषों में से एक की बहन राजकुमारी ने कहा। 'कई दूल्हों ने यहाँ आने के लिए गाड़ियाँ किराए पर ली थीं, और कई परिवारों ने शादी के लिए रिश्तेदारों और मेहमानों को बुलाया था। सभी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। ' एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना 24 मई को सामने आई, और धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज किया गया। 'मुख्य आरोपी मुकेश और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम उनके काम करने के तरीके (modus operandi) के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। चूँकि आरोपी विदिशा ज़िले के रहने वाले हैं, इसलिए आगे की जानकारी इकट्ठा करने के लिए वहाँ भी एक टीम भेजी गई है,' अधिकारी ने कहा।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: 100 करोड़ की ज़मीन 10 करोड़ में बेच दी

● नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड केस में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। एनईएसईएल (नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड) घोटाले से जुड़ी हरियाणा की एक ज़मीन की नीलामी पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि करीब 100 करोड़ की ज़मीन को 'संदिग्ध प्रक्रिया' के जरिए केवल 10 करोड़ में बेचा गया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच क्विकर रियल्टी नामक वैल्यूअर कंपनी की याचिका सुन रही थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंपनी को 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने टिप्पणी की: '100 करोड़ की संपत्ति को 10 करोड़ में बेच दिया गया और खरीदार उसी इलाके का निजी बिल्डर था। ऐसे में आप यहां किस आधार पर आए हैं? ' मामला हरियाणा की 35 एकड़ ज़मीन से जुड़ा है, जिसकी शुरुआती कीमत 74 करोड़ से अधिक आंकी गई थी। बाद में नई वैल्यूएशन रिपोर्ट में इसे कृषि भूमि मानते हुए कीमत घटाकर करीब 10 करोड़ कर दी गई और उसी रकम में नीलामी कर दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ज़मीन को गलत तरीके से कृषि भूमि घोषित किया गया, जबकि वह रिहायशी क्षेत्र में स्थित थी। कोर्ट ने इसे 'घोटाले के भीतर घोटाला' बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी वैल्यूएशन प्रक्रिया पर गंभीर चिंता जताई। जस्टिस बागची ने सवाल किया कि सिर्फ निर्माण लाइसेंस खत्म होने से रिहायशी ज़मीन कृषि भूमि कैसे बन सकती है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताएं सामने आती हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने MPID कोर्ट्स के कामकाज पर भी नाराज़गी जताई। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद बिक्री विलेख जारी किए गए थे। उन्होंने इसे गंभीर भ्रष्टाचार बताया। आखिर में क्विकर रियल्टी ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी ताकि वह हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर रोक देने से साफ इनकार कर दिया।

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन महानगर इकाई द्वारा बालेश्वर लाल जी की 39 वीं पुण्यतिथि मनाई गई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

फिरोजाबाद - ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक बालेश्वर लाल की 39 वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन रामनगर स्थित शिव मांटेसरी पब्लिक स्कूल रामनगर फिरोजाबाद पर किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के आगरा मंडल अध्यक्ष अखलेश सक्सेना द्वारा बालेश्वर के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके पश्चात उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों ने बारी बारी बाबू बालेश्वर लाल जी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी। मंडल अध्यक्ष अखिलेश सक्सेना द्वारा बाबू बालेश्वर लाल के जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक छोटे से कस्बे से प्रारंभ हुई दीपक की ज्योति आज पूरे भारतवर्ष में सूर्य के सामान प्रकाशित हो रही है। जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जब बालेश्वर लाल जी ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की स्थापना की थी तो उन्होंने उसको पत्रकारों के हित के लिए बनाया था। बाबूजी का सपना था कि देश के प्रत्येक पत्रकार को न्याय मिले तथा जो सुविधाएं एक पत्रकार को मिलनी चाहिए वह मिले। उन्होंने बताया कि बाबूजी द्वारा लगाया गया एक छोटा सा पौधा एक वट वृक्ष के समान पूरे देश में फैल चुका है। जिला महासचिव अनिल कुमार झा ने बताया कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन भारतवर्ष का सबसे बड़ा पत्रकारों का संगठन है जो कि पत्रकारों के हित के लिए दिन-रात कार्यरत रहता है और एक आम पत्रकार के बाद को मुख्य पटल पर रखने का कार्य करता है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन एक परिवार की तरह कार्य करता है जो अपने प्रत्येक पत्रकार साथी का ध्यान रखना है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह ने की। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, फिरोजाबाद जिला अध्यक्ष डी के सिंह, जिला महासचिव अनिल कुमार झा, महानगर अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष दुर्गेश चितौड़ी, सुशील ओझा, सुनील राठौर, विजय प्रताप सिंह, संदीप सविता, ज्ञान प्रकाश सिंह, विक्रम सागर, सज्जन सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।

बघमरा वी पैक्स केन्द्र पर पुलिस की उपस्थित मे वितरित की गई खाद

भारी संख्या मे सुवह से ही लाइन मे खाद लेने के लिये खडे रहे किसान

गोला गोकर्णनाथ खीरी- गोला तहसील क्षेत्र के गांव बघमरा मे सहकारी समिति वी पैक्स केन्द्र पर खाद लेने के लिये सुवह लगभग आठ बजे से किसान अपने अपने खाद लेने के कागजातो को लेकर धूप मे खडे रहे, जैसे ही सचिव मदन लाल भारती अपने स्टाफ के साथ खाद वितरित करने के लिये अपने आफिस मे घुसे वैसे ही हजारो की संख्या मे पहले हमको पहले हमको को दिये जाने को लेकर विवाद हो गया,जिसके पश्चात सचिव ने हैदराबाद पुलिस को फोन कर मौके पर बुलाया,इसके पश्चात सचिव के अनुसार लगभग सौ किसानो को टोकेन दे कर खाद का वितरण काराया, वही प्रति किसान को ऐक ऐकड के हिसाब से तीन खाद का वितरण किया जा रहा है। मदन लाल भारती, सचिव सहकारी समित बी पैक्स केन्द्र बघमरा खीरी ने बताया कि खाद का स्टाक पर्याप्त रूप मे मौजूद है,फिगर प्रिंट मशीन मे सरबर की खराबी के चलते व्यवधान आ रहा है।

सेमरई में 42 लाख की सनसनीखेज चोरी, 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली

● पीड़ित परिवार ने की एस आईटी जांच की मांग

रात्रि गश्त पर उठे सवाल, दहशत में पूरा गांव; कोटेदार बोले- 'पाई-पाई जोड़कर बनाई पूंजी लुट गई, कानून से भरोसा उठ रहा '

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

गोला गोकर्णनाथ खीरी/ थाना हैदराबाद क्षेत्र की ढकवा पुलिस चौकी अंतर्गत सेमरई गांव में 21 मई की रात हुई करीब 42 लाख रुपये की बड़ी चोरी का पुलिस 6 दिन बाद भी खुलासा नहीं कर सकी है। वारदात के बाद से पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है और गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठाते हुए एस आईटी जांच की मांग की है। 21 मई बृहस्पतिवार की रात अज्ञात चोरों ने सेमरई गांव के कोटेदार चंद्र प्रकाश मिश्रा के घर को निशाना बनाया। चोर मकान के पीछे खिड़की की ग्रिल तोड़कर अंदर घुसे। इसके बाद उन्होंने सो रहे परिवार के सदस्यों के कमरों के दरवाजे बाहर से कपड़े व रस्सी से बांध दिए। चोरों ने दो कमरों की अलमारी और बक्से तोड़कर क़रीब 40 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात, 2 लाख रुपये नकद और लाइसेंसी बंदूक तक उठा ली। हालांकि चोर अज्ञात कारणों से बंदूक को घर के बाहर ही फेंक गए, लेकिन बाकी सामान लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष सुनील कुमार मलिक और सीओ गोला रमेश कुमार तिवारी ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया था। पुलिस ने आस-पास के गांवों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और विशेष टीम गठित कर जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया था। लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस चोरों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर केवल सड़कों पर टहलती दिख रही है। कोटेदार चंद्र प्रकाश मिश्रा ने बताया, 'मेरे दोनों बेटों और बहुओं ने अध्यापक की नौकरी से, और मैंने दिन-रात पसीना बहाकर पाई-पाई जोड़कर परिवार के लिए संपत्ति जमा की थी। जब वही पूंजी कुछ पलों में शातिर अपराधियों द्वारा लूट ली जाए और प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई न दिखे, तो कानून व्यवस्था से आम लोगों का भरोसा उठने लगता है। ' गांव वालों का कहना है कि अगर पुलिस रात में नियमित गश्त करती तो शायद इतनी बड़ी वारदात न होती। गांव के बाहरी छोर पर बने घर पहले से ही असुरक्षित हैं। घटना के बाद से ग्रामीण खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोगों ने सवाल उठाया कि जब एक कोटेदार का घर सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी का क्या होगा?

पीड़ित परिवार की प्रमुख मांगें

SIT गठित होः मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच के लिए विशेष जांच टीम बनाई जाएरात्रि गश्त बढ़ेः ग्रामीण इलाकों में पुलिस की रात्रि गश्त तत्काल बढ़ाई जाए उच्च स्तरीय निगरानीः स्क्रस्तर के अधिकारी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग करें इस संबंध में ढकवा चौकी इंचार्ज जय नारायण यादव ने बताया, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ संदिग्ध नंबरों पर काम किया जा रहा है। अभी तक घर के सामने से कोई गाड़ी जाती नहीं मिली है। हम लोग लगे हुए हैं, कहीं से कुछ तो मिल जाए। रिस्पांस अभी शून्य है। तीन टीमें गठित की गई हैं। जल्द खुलासा किया जाएगा। ' इस बड़ी चोरी के बाद से न सिर्फ पीड़ित परिवार, बल्कि पूरा गांव सदमे और दहशत में है। 6 दिन बाद भी पुलिस की तरफ से कोई ठोस प्रगति सामने न आना उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। ग्रामीण पूछ रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज और गठित टीमों ने अब तक क्या किया? क्या पुलिस सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित है?

अंतरिक्ष में नई उड़ानः आसमान में उड़ा भारत का पहला स्वदेशी सुपर-प्रेशर बैलून

● रेड बैलून एयरोस्पेस ने विजयवाड़ा से भारत का पहला स्वदेशी सुपर-प्रेशर बैलून (एसपीबी) लॉन्च किया, जो लगभग 25 किमी की ऊंचाई तक पहुंचा।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली। रेड बैलून एयरोस्पेस ने बुधवार को देश का पहला स्वदेशी सुपर-प्रेशर बैलून (एसपीबी) लांच किया, जिसमें सात राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के व्यावसायिक पेलोड ले जाए गए। एसपीबी हाई एल्टीट्यूड वाले गुब्बारे होते हैं। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी स्टेडियम से लांच किया गया एसपीबी (विस्टा) लगभग 25 किमी की ऊंचाई तक पहुंचा।

पहला स्वदेशी सुपर-प्रेशर बैलून लॉन्च

रेड बैलून एयरोस्पेस के सह-संस्थापक और सीईओ सीवीएस किरण ने कहा, 'यह मिशन सुपर-प्रेशर बैलून की क्षमता को साबित करने के लिए लांच किया गया, जो भारत में पहले कभी नहीं किया गया।' हालांकि, बुधवार को लांच गुब्बारा 24 घंटे तक आकाश में रहने की उम्मीद है, लेकिन कंपनी का लक्ष्य महीनों तक हवा में रहने में सक्षम एसपीबी विकसित करना है। यह मिशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसपीबी सेटेलाइट की तुलना में कई फायदे प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, एसपीबी बहुत सस्ते होते हैं और सेटेलाइट द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को करने में सक्षम होते हैं।

एयरोस्पेस ने विजयवाड़ा से प्रक्षेपण

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भारत के पहले सुपर प्रेशर बैलून के लांच में भाग लिया और इसे अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में भारत की तीव्र प्रगति के बीच देश और आंध्र प्रदेश दोनों के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया।

उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों के कारण आज हम अंतरिक्ष क्षेत्र में आठ अरब डालर का उद्योग हैं। अगले दशक में ही हमारा लक्ष्य 40 अरब डालर का अंतरिक्ष उद्योग बनना है।'

रणवीर की 'सीक्रेट डील' पर फरहान अख्तर ने फेरा पानी, डॉन 3 विवाद में नई पहेली?

● फिल्म डॉन 3 का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में एक अहम जानकारी सामने आ रही है, जो आपको चौंका देगी।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली। फिल्म डॉन 3 को लेकर सुर्खियों का बाजार काफी गर्म है। जिसकी वजह अभिनेता रणवीर सिंह का इस मूवी को छोड़ना है। बाद में इस मामले को लेकर डॉन 3 के निर्माता फरहान अख्तर ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और मामले को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) तक लेकर गए। FWICE की हाई लेवल की मीटिंग के बाद रणवीर सिंह पर बैन लगाने का एलान किया गया। अब खबर आ रही है कि डॉन 3 को छोड़ने के बदले में रणवीर ने फरहान को सीक्रेट डील ऑफर की थी, जिसे खुन्नस में आकर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था।

क्या थी रणवीर सिंह की सीक्रेट डील?

साल 2023 में मेकर्स की तरफ से डॉन 3 का आधिकारिक एलान किया गया था, जिसमें रणवीर सिंह डॉन के किरदार में मौजूद रहे। फिर अचानक से रणवीर ने फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के एक्सेल एंटरटेनमेंट बैनर तले बनने वाली डॉन 3 को छोड़ दिया, जिसकी वजह से मेकर्स को बड़ा झटका लगा। फरहान ने एफडब्यूआईसीई में रणवीर सिंह की शिकायत की और नाराजगी व्यक्त की। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के अनुसार रणवीर सिंह की टीम ने फरहान अख्तर और अन्य के साथ इस मामले को सुझलाने की भरपूर कोशिश की। रिपोर्ट के आधार पर रणवीर की तरफ से एक्सेल एंटरटेनमेंट को 35 करोड़ का एक बड़ा ऑफर दिया गया। जिसमें डील ये थी कि रणवीर सिंह फरहान और अन्य को 10 करोड़ की धनराशि वापस करेंगे, इसके अलावा वह एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले भविष्य में उनके साथ बनने वाली किसी भी मूवी में 25 करोड़ का डिस्कॉउंट भी रखेंगे। लेकिन फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने रणवीर सिंह की इस डील को ठुकरा दिया। हालांकि, जागरण इस मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है। फरहान और रितेश के दावे के आधार पर डॉन 3 से रणवीर के अचानक से बाहर होने की वजह से उन्हें न सिर्फ पैसे और बल्कि प्रोफेशनल तौर पर भी काफी नुकसान हुआ है।

नहीं करेंगे रणवीर सिंह के साथ काम

एक्सेल एंटरटेनमेंट के मालिक फरहान अख्तर और रितेश सिधावानी ने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) से अपनी शिकायत में ये साफ किया है कि वह भविष्य में कभी भी रणवीर सिंह के साथ कोई भी नहीं बनाएंगे।

बकरीद से पहले 85 लाख खर्च कर जैन समाज ने 650 बकरों को खरीदा

● कुर्बानी से बचाने का चला रहे अभियान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली। ईद-उल-अजहा पर कुर्बानी के लिए मुस्लिम इलाकों में बकरों की खरीद जोरों पर है। इस बीच 'अहिंसा परमो धर्मः' के परम वाक्य को आत्मसात करते हुए जैन समाज की एक टोली कुर्बानी के लिए बिक्री को आ रहे बकरों को जीवनदान देने की मुहिम चला रखी है। ऐसे ही एक अभियान में जैन समाज की एक टोली जीव दया संस्थान के माध्यम से दिल्ली व उप्र से तीन-चार दिनों में ही बकरीद के लिए लगी मंडी से 650 से अधिक बकरों की खरीदारी कर ली है। बुधवार को भी यह अभियान जारी रहा। टोली के एक सदस्य के अनुसार, यह क्रम बकरीद के दिन भी जारी रहेगा। कोशिश होगी कि इस बकरीद पर एक हजार बकरों की खरीदारी हो जाए। इस टोली ने 650 बकरों की खरीद पर अब तक करीब 85 लाख रुपये खर्च किए हैं। जो खुद से तथा समाज से जुटाए हैं। यह टोली मुख्य रूप से एक हफ्ते से सक्रिय है और सीलमपुर, जामा मस्जिद समेत दिल्ली के कई अन्य मुस्लिम क्षेत्रों के साथ ही उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित गुलावठी बकरा मंडी, बागपत, रामपुर, मथुरा समेत अन्य जिलों के बकरा मंडी से ये बकरे खरीदे हैं। इन बकरों को पूरी कीमत चुकाकर उन्हें खरीदा जा रहा है। विशेष बात कि जैन समाज की इस मुहिम में दो मुस्लिम युवक भी साथ दे रहे हैं। वह मंडियों से बकरों की खरीद में और उनके स्वास्थ्य की पहचान में मदद कर रहे हैं। जैन समाज न सिर्फ बकरों को जीवनदान दे रहा है, बल्कि उन्हें आजीवन बच्चों की तरह पालने का संकल्प लिया है। दिल्ली व उत्तर प्रदेश के बकरा मंडियों से यह बकरे खरीदकर उत्तर प्रदेश के बागपत के अलीनगर सराय में बने बकराशाला में रखा जा रहा है। जहां उनके लिए पर्याप्त स्थान है। वैसे, जीव दया संस्थान पिछले करीब 10 वर्ष से इस अभियान में लगी है तथा अब तक करीब 8,000 बकरों को कुर्बानी से बचा लिया है। जीव दया संस्थान के अध्यक्ष मनोज जैन के अनुसार, यह अभियान किसी धर्म की मान्यताओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि, भगवान महावीर के 'जियो और जीने दो' संदेश के प्रति समर्पण है। जिसके तहत न सिर्फ बकरे, बल्कि, मछली व अन्य पशु-पक्षी को बचाने की कोशिश अनवरत चल रही है।

दिल्ली में पानी की किल्लत बरकरार, लक्ष्य से 100 एमजीडी कम मिल रहा पेयजल

दिल्ली। वजीराबाद जलाशय का जलस्तर गिरने से राजधानी के कई क्षेत्रों में पानी की समस्या बनी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा द्वारा पहले की तुलना में अधिक पानी छोड़ने के बावजूद समस्या बनी हुई है। समर एक्शन प्लान जारी करते समय दिल्ली सरकार ने 1002 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था। इसकी तुलना में दिल्ली में सभी जल शोधन संयंत्रों और ट्यूबवेल से लगभग 902 एमजीडी पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इस तरह से निर्धारित लक्ष्य से दिल्लीवासियों को लगभग 100 एमजीडी कम पानी मिल रहा है। वजीराबाद जलाशय का सामान्य जलस्तर 674.5 फीट होना चाहिए। इसकी तुलना में यह 669 फीट के आसपास है। इससे 134 एमजीडी क्षमता वाले वजीराबाद और 98 एमजीडी क्षमता वाले चंद्रावल डब्ल्यूटीपी से लगभग 30 प्रतिशत कम पेयजल मिल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा सरकार से बात की है। उसके बाद हरियाणा से कैरियर लाइन नहर (सीएलसी) और दिल्ली उप-शाखा (डीएसबी) के माध्यम से 979.5 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पहले लगभग 900 क्यूसेक पानी आ रहा था। अधिक पानी छोड़े जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है क्योंकि दोनों संयंत्रों तक पानी पहुंचने में अभी दो दिन लगेंगे। वजीराबाद जलाशय का जलस्तर बढ़ाने के लिए यमुना में अधिक पानी आना चाहिए। दो प्रमुख डब्ल्यूटीपी के क्षमता के अनुसार नहीं चलने से उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी दिल्ली के कई क्षेत्रों में जल संकट की स्थिति है। कहीं पानी नहीं आ रहा है तो कहीं कम। सिविल लाइंस, माडल टाउन, हिंदू राव अस्पताल क्षेत्र, कमला नगर, शक्ति नगर, करोलबाग, पहाड़गंज और एनडीएमसी क्षेत्र तथा दिल्ली छावनी और आसपास के कुछ क्षेत्र सहित कई स्थानों पर लोग पानी के लिए परेशान हैं।